वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलाईज यूनियन

रेल निजीकरण के खिलाफ

जनआन्दोलन

2020

टारगेट ग्रुप

1. व्यापारी
2. युवा वर्ग
3. विद्यार्थी वर्ग
4. महिला वर्ग
5. पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक
6. दैनिक यात्री
7. श्रमिक वर्ग
8. खिलाडी, कलाकार, पत्रकार एवं मीडिया कर्मी
9. बुद्धिजीवि वर्ग (प्रोफेसर, जज, एडवोकेट, डाक्टर)
10. एनजीओ एवं जन समितियां
11. रेलकर्मी
12. राजनैतिक दल

व्यापारी वर्ग पर रेलवे निजीकरण का दुष्प्रभाव

➡ आर्थिक मंदी के दौर में जहां व्यापार पहले ही सुस्त अवस्था में है रेलवे के साथ जुड़े बाजार जो रेल कर्मचारियों की आमदनी पर निर्भर है। जो कोटा में ही लगभग 30 करोड़ रू. महीना रेलकर्मचारी का बाजार में आता है, निजीकरण के बाद यह रकम घटकर 8 करोड़ रू. पर आ जायेगी।

- रेल किराया बढ़ने से आवागमन करने वाले यात्रियों की संख्या में भारी कमी होगी जिसका दुष्प्रभाव बाजार पर पड़ेगा जैसे होटल, रेस्टोरेंट, राशन, यातायात इत्यादि व्यापार प्रभावित होगें।

- निजीकरण के बाद डायनेमिक फेयर व्यवस्था लागू होगी, जिसका किराया विमान से भी ज्यादा होगा,व्यापारी वर्ग इससे सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि उनकी यात्रायें पूर्व निर्धारित नहीं होती है साथ ही भारत सरकार ने प्राईवेट ट्रेन ऑपरेटरों को अधिकतम किराया तय करने की कानूनी शक्ति प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है जिससे निजी ट्रेन संचालन करने वाला ऑपरेटर कभी भी मनमाना किराया बढ़ा सकता है जिसे कहीं भी चुनौति नही दी जा सकेगी।

- मालभाड़ा बढ़ने से सारा खामियाजा व्यापारी वर्ग को भुगतना होगा क्योंकि उनसे मनमाना किराया वसूला जायेगा जिससे वस्तुओं की लागत में बढ़ोत्तरी होगी तथा क्रय क्षमता पहले से ही कम होने से व्यापार घट जायेगा।

- स्टेशनों की निजीकरण होने से स्टेशन के परिधि में बडे पूजिपतियों द्वारा सभी प्रकार के शॉपिंग मॉल एवं काम्पलेक्स बनाकर सामान बेचा जायेगा इसका दुष्प्रभाव शहर के स्थानीय व्यापारी वर्ग पर पडेगा।

- उधार आधारित बाजार व्यवस्था में अस्थाई कर्मचारी होने एवं वेतन कम होने से उधार दिये गये सामान के भुगतान की सुरक्षा खत्म हो जायेगा और व्यापार प्रभावित होगा।
- निजीकरण के कारण बढ़े हुये रेल किराये के अलावा यात्री सुविधायें जैसे पार्किंग, वेटिंगरूम, प्लेटफार्म टिकिट इत्यादि के लिये भी कई गुना दाम चुकाना पड़ेगा।

व्यापारी वर्ग के साथ गतिविधि

1. शहर के व्यापारी वर्ग/मंडल की कार्यकारिणी के साथ बैठक आयोजित की जाये जिसमें निम्न रूपरेखा तय हो :–

➡ सभी क्षेत्रीय व्यापार मंडलों से आये पदाधिकारियों का समस्त ब्यौरा रखने के लिये रजिस्टर निर्माण किया जाये।

➡ व्यापार मंडल पदाधिकारियों से उनके क्षेत्र में जनसम्पर्क अभियान की तारीख व समय का निर्धारण किया जाये।

➡ शहर के सभी व्यापारी वर्ग व यूनियन पदाधिकारियों का सामूहिक विशाल प्रदर्शन या अधिवेशन आयोजित किया जाये।

2. यूनियन के पदाधिकारियों की टीमों का क्षेत्रानुसार निर्धारण किया जाये

3. शहर के क्षेत्रानुसार व्यपारिक मंडल के साथ कार्यक्रम तय किया जाये।

4.शहर के मुख्य मुख्य व्यापारिक स्थलों पर निजीकरण के दुष्प्रभावों के बैनर/हार्डिंग लगाये जाये।

5.सम्पूर्ण कार्यक्रम की मीडिया कवरेज हेतु यूनियन कार्यालय में सैल बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

युवा वर्ग पर रेलवे निजीकरण का दुष्प्रभाव

➡ रेलवे एवं सरकारी उद्यम भारत का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता संस्थान है। इनके निजीकरण के साथ ही रोजगार के अवसर कम हो जायेगे और बेरोजगारी चरम पर पहुंच जायेगी।

- रेलवे एवं सरकारी उद्योग में कार्य करने वाला युवा स्वाभिमान व सम्मान से नौकरी करते हुये देश की सेवा करता है किन्तु निजीकरण के उपरान्त गुलामी की नौकरी व पूंजीपति की सेवा करेगा।

- रेलवे तंत्र में कार्य करेन पर आकर्षक वेतन प्राप्त होता है जबकि निजीकरण के उपरान्त युवाओं को एक चौथाई या उससे भी कम में काम करने पर मजबूर होना पड़ेगां

➡ रेलवे में कार्य करने पर वर्तमान में काम के घंटे निर्धारित है। निजीकरण के उपरान्त कार्य के घंटे मालिक की इच्छा पर होगें। मनमाने ढंग में मालिक काम लेने को स्वतंत्र होगा।

➡ वर्तमान रेलवे की सेवाओं को नौकरी की स्थाई सुरक्षा गारंटी रहती है जबकि निजीकरण के पश्चात युवाओं की नौकरी अस्थाई एवं असुरक्षित तथा मालिक की कृपा पर निर्भर रहेगी। वर्तमान की जॉब सिक्यूरिटी पूरी तरह समाप्त हो जायेगी।

- रेल के निजीकरण के पश्चात छिपी हुई रोजगार/योग्यता के अनुसार रोजगार न लिना में बेतहाशा वृद्धि होगी।
- रेलवे में कार्य करते हुये युवाओं का शोषण एवं प्रताड़ना होने पर देश के श्रम कानूनों का संरक्षण प्राप्त होता है जो निजीकरण के पश्चात हायर एण्ड फायर की नीति में बदल जायेगा।
- रेलवे के निजीकरण के पश्चात रेलवे से होने वाली आय सरकार की बजाये बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली जायेगी। सरकार की आय में कमी का दुष्परिणाम शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाओं पर कटौती के रूप में आयेगा जिसके परिणामस्वरूप भी और तेजी के साथ निजीकरण की और बढ़ेगी जिससे ये सेवायें भी महंगी होगी और वहां पर भी रोजगार के अवसर कम हो जायेगें।

➡ रेलवे के सेवा में जुडी महिलायें जो सुरक्षा एवं सम्मान का पात्र होती है वही निजीकरण के उपरान्त ये सुरक्षा एवं सम्मान पूरी तरह समाप्त हो जायेगा और उसे एयर होस्टेज की भाँति ब्यूटी क्वीन की तरह पेश किया जायेगा।

➡ वर्तमान में रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृति के बाद भी पेंशन का प्रावधान है किन्तु निजीकरण के पश्चात किसी भी तरह की पेंशन के प्रावधान के लाभ की काई गारंटी युवाओं को नहीं मिलेगी।

युवा वर्ग के साथ गतिविधियां

युवा वर्ग को चिन्हित करना

1. रेलवे कर्मचारी के परिवार के बेरोजगार युवाओं से संपर्क करना।
2. इनके माध्यम से शहर के विभिन्न वर्ग के युवाओं तक पहुँचना।

3. रेलवे एक्ट अप्रेन्टिस के युवा साथियों में सम्पर्क करना।

4. निजीकरण के विरोध में सहमति रखने वाले विभिन्न युवा संगठनों में संपर्क स्थापित करना एवं उनके माध्यम से युवाओं तक पहुँचना।

5. रेल में कार्यरत युवा कर्मचारियों से संपर्क /स्थानीय स्थर पर युवाओं की छोटी–छोटी विचार गोष्ठियाँ आयोजित करना।

6. यूनियन द्वारा ब्रांच लेवल पर निजीकरण विरोधी प्रदर्शन आयोजित कर विभिन्न युवा संगठनों को रेलवे के निजीकरण–विरोध अभियान के पक्ष में आमंत्रित करना।

7. सोशल मीडीया से जोड़ना।

8. मण्डल/ब्रांच स्तर पर युवाओं का रेल निजीकरण विरोधी सम्मेलन आयोजित करना।

9. मण्डल/ब्रांच स्तर की रेल निजीकरण विरोधी युवाओं की जन–कमेटी का निर्माण करना।

10. प्रिंट एवं सोशल मीडीया के माध्यम से निजीकरण के खिलाफ प्रचार अभिचान चलाना एवं युवाओं को जोड़ना।

11.युवा वर्ग की संयुक्त संघर्ष समिति का गठन करना तथा मीटिंग/ अधिवेशन आयोजित करनां

विद्यार्थी वर्ग पर रेलवे निजीकरण का दुष्प्रभाव

1. भारतीय रेलवे ट्रेन से यात्रा करने बाले स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को स्टूडेंट कन्सेशन के रूप में स्कूल से घर आने के लिये रियात दर से टिकट उपलब्ध कराती है । शैक्षणिक यात्रा, प्रतियोगी परीक्षा शोध आदि कार्य के लिय रेल सफर करने पर भी उन्हें यात्रा टिकट में छूट दी जाती है साथ ही स्कूल के विद्यार्थियों को भी मंथली टिकट रियायती जारी की जाती है निजीकरण के बाद ये सुविधाए बन्द होने से विद्यार्थियों के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा ।

2. वर्तमान समय मे उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कोचिंग आदि के लिये विद्यार्थी अपने मूल शहर से दूरस्थ बड़े शहरों में अपनी सुविधानुसार रहते है जहां से इन्हें अक्सर ट्रेन द्वारा ही यात्रा करते है। निजीकरण के बाद बढ़े हुए किराये से यात्रा करने पर इनके व इनके परिवार पर पढ़ाई के मद में अत्यधिक खर्च बढ़ जाएगा । इसके कारण परिवार पर आर्थिक बोझ बढेगा।

3. आज के इस बेरोजगारी के दौर में अधिकतर विद्यार्थी शिक्षा उपरांत रेलवे जैसे सरकारी संस्थान जो बर्तमान में लाखों लोगों को रोजगार देता के लिये वर्षों से तैयारी करते है व सरकारी संस्थान में नौकरी प्राप्त कर अपना भविष्य बेहतर व सुरक्षित करना चाहते को निजीकरण के बाद यह अवसर समाप्त हो जाएगा व इन्हें मजबूरी में कम बेतन पर व बिना किसी अतिरिक्त सुविधा के निजी कम्पनी व ठेकेदारों के अधीन कार्य करने पड़ेंगे। जहां इनका भविष्य भी सुरक्षित नही होगा। इन्हें कम्पनी कभी भी बाहर का रास्ता दिखा सकती है ।

4. दलित वर्ग पिछड़े वर्ग व आर्थिक रुप से गरीब वर्ग विकलांग वर्ग के विद्यार्थियों को रेलवे में रोजगार के लिये आरक्षण की सुविधा है। रेल जैसे संस्थान में नौकरी प्राप्त कर ये सामाजिक आर्थिक व मानसिक रूप से समाज मे सबल बनने की उम्मीद रखते है। निजीकरण उपरांत सरकारी पद समाप्त हो जाएगें पूंजीपतियों के अधीन कार्य करने को विवश होंगे जहां इनकी श्रमशक्ति का शोषण होगा।

5. भारतीय रेल वर्तमान में केंद्र सरकार के लिये आयोजित प्रतियोगी परीक्षा साक्षात्कार के लिये उनके घर से आने जाने के लिये निःशुल्क यात्रा पास देती है, जो निजीकरण के बाद बन्द हो जाएगा, जिससे गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा।

6. आज के दौर में ग्रामिण क्षेत्र से हजारों बच्चे शिक्षा हेतु कोचिंग हेतु शहरों में आते है जिस हेतु रेल एक मात्र साधन है तथा छोटे स्टेशनों पर पास गाडी चलती है जो कि मुनाफा नही सेवा देती है बंद हो जायेगी।

7. ग्रामिण क्षेत्र छोटी जगहों पर शिक्षक भी पैसेंजर गाडी का प्रयोग करते है जो उन्हें नही मिलेगी जिसका सीधा असर ग्रामिण क्षेत्र में स्थापित शिक्षा संस्थानों पर पढेगा ।

विद्यार्थी वर्ग के साथ गतिविधि

1. यूनियन के पदाधिकारी व सक्रिय सदस्य, शासकीय विद्यालय, महाविद्यालय, निजी कॉलेजों कोचिंग संस्थानों में जाकर उनके साथ मीटिंग कर रेलवे के निजीकरण से वे किस प्रकार प्रभावित होने बाले है,उन्हें भविष्य में क्या नुकसान होने बाले है से अवगत कराये।
2. विद्यालय के गेट के सामने पोस्टर, फ्लेक्स लगाये।
3. जिसमे निजीकरण से होने वाले नुकसान की जानकारी छपी हो साथ ही उन्हें छोटे छोटे इससे सम्बंधित पम्पलेट देकर उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से व धरना प्रदर्शन के माध्यम से निजीकरण के विरोध के लिये जागृत करे।

विद्यार्थी वर्ग की संयुक्त संघर्ष समिति का गठन करना तथा मीटिंग / अधिवेशन आयोजित करना।

महिला वर्ग पर रेलवे निजीकरण का दुष्प्रभाव

➡ भारतीय रेल महिला यात्रियों के लिए बहुत सारी अतिरिक्त सुविधा दे रही है जिससे कि वो अकेले व परिवार के साथ सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा कर सके, जैसी अनेक सुविधायं अभी प्राप्त है जोः–

1. निजीकरण के बाद गाड़ियां में आरक्षित महिला डिब्बो व अन्स सुविधाये समाप्त हो जायेगी।

2.निजीकरण के पश्चात वरिष्ठ महिलाओं को रेल यात्रा टिकट में अतिरिक्त रियायत दी जाती है। वो समाप्त हो जायेगी।

3. निजीकरण के पश्चात प्रत्येक गाड़ियों में महिला यात्रियों के लिये निश्चित सीट आरक्षित रहती है। वो समाप्त हो जायेगी।

4. निजीकरण के पश्चात प्रत्येक गाड़ी में वरिष्ठ महिला यात्रियों के लिये आरक्षित लोअर सीट की सुविधा बन्द हो जायेगी।

5. निजीकरण के पश्चात उपनगरीय रेल्वे में महिला स्पेशल गाड़ियों की सुविधा बंद हो जायेगी ।
6. निजीकरण के पश्चात गर्भवती महिलाओं को लोअर सीट की सुविधा कोच में उपलब्ध रहती है जो बंद हो जायेगी।
7. महिला यात्री के साथ परिचायक उसी श्रेणी में जिसमें महिला यात्री यात्रा कर रही हो रात में अनुमति प्राप्त है ।
8. निजीकरण के बाद निजी मालिक द्वारा महिला को दी जाने वाली नौकरियां में जो भी नियम व शर्ते रहेगी उनमें महिलाएं आत्म सम्मान व स्वाभिमान नौकरियां नहीं कर पायेगी उदाहरण – तेजस गाड़ी

➡ चूंकि निजी कम्पनी का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना होता है वहीं इस प्रकार की रियायत व सुविधा से उन्हें नुकसान होने की सम्भावना रहती है अतः निजीकरण के बाद ये सभी सुविधाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी इससे महिला यात्रियों को काफी असुविधा व आर्थिक नुकसान होगी।

महिला वर्ग की गतिविधि

- यूनियन की महिलाविंग के पदाधिकारियों को महिला महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज जहां महिला वर्ग ज्यादा रहती ऐसे संस्थान जहाँ महिलाकर्मी ज्यादा कार्य करती है उनके पास जाकर पम्पलेट व पोस्टर के माध्यम से जागृत करना।

अपने मोहल्ले के आसपास जहाँ महिला सामाजिक संगठन कार्य करती है, के बीच जाकर उन्हें रेलवे के निजीकरण से महिलाओं को होने वाले नुकसान की जानकारी दे।

- इसके लिये पोस्टर, फ्लेक्स, पम्पलेट इत्यादि जिसमे होने वाले नुकसान की जानकारी हो लगाने व वितरित कर उन्हें निजीकरण के विरूद्ध आंदोलित करने के लिये जागृत करना होगा।

- घरेलू एवं आंगनबाड़ी की महिलाओं के माध्यम से आस–पास क्षेत्र की सभी महिलाओं को जन–आन्दोलन से जोड़ना।
- महिलाओं की संघर्ष समितियां बनाना एवं जनआन्दोलन हेतु महिला सम्मेलन आयोजित करना।

पेंशनर व वरिष्ठ नागरिकों पर रेलवे निजीकरण का दुष्प्रभाव

1. वर्तमान में भारतीय रेल के कर्मचारियो को सेवानिवृत्त होने के उपरांत उन्हें सामाजिक सुरक्षा के रूप में कोई भी पेन्शन के रूप में प्रतिमाह एक निश्चित राशि दी जाती है जिससे कि सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें आर्थिक रूप से कोई दिक्कत ना हो। रेलवे के निजीकरण होने से निजी कम्पनी के अधीन कार्य करने बाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद कोई भी राशि नही मिलेगी।

2.भारतीय रेल के सेवानिवृत्त कर्मचारियो को रेल निःशुल्क यात्रा के लिये मानार्थ पास दी जाती है, उच्च श्रेणी के यात्रियों को सहायक के रुप मे परिचारक की भी सुविधा दी गई है। निजीकरण के बाद जरूरी नही की ये सुविधा इन्हें मिलती रहे व निजी कम्पनी उन्हें सेवानिवृत्त होने के बाद कोई भी यात्रा सुविधा नही देने बाली है।

3. भारतीय रेल वर्तमान में वरिष्ठ यात्रियों को बहुत सी सुविधा दी है जैसे रेल किराया में रियायत, आरक्षित डिब्बो में एक निश्चित सीट आरक्षित है व इनके लिए भी लोअर बर्थ आरक्षित रहती है। निजी कम्पनी अपनी आर्थिक हितों व लाभो के कारण उन्हें यह सुविधा नही देगी। इससे वरिष्ठ नागरिकों व पेंशनरो को आर्थिक नुकसान के साथ अन्य असुविधा बढ़ेगी ।
4. पेंशनर वरिष्ठ नागरिक समाज के सम्मानिय है जिनका महत्वपूर्ण योगदान समाज के हेतु रहता है उम्र के इस पढ़ाव में आय भी कम हो जाती तब इस परिस्थिति में रेल किराया में वृद्धि उन्हैं परेशान करेगी, जो कि न्यायोचित नही है।

पेंशनर व वरिष्ठ नागरिकों के साथ गतिविधि

- यूनियन पदाधिकारी अपने सक्रीय सदस्यों के साथ पेन्शनर एसोसिएशन के नेतृत्व व उनके सदस्यों से मिलकर मीटिंग करें उन्हें निजीकरण उपरांत होने बाले नुकसान से अवगत कराएं, पोस्टर पम्पलेट के माध्यम से उन्हें आंदोलन के लिय उत्साहित करे ।
- साथ ही ऐसे जगह की तलाश कर जहां वरिष्ठ नागरिक एक साथ ज्यादा मिलते है जैसे पार्क,मन्दिर,मस्जिद मॉर्निंग वॉक सीान पर जाकर उन्हें निजीकरण से होने बाले नुकसान से अवगत कराकर जनांदोलन का समर्थन करने हेतु जागरूक करें।
- पेंशनर व वरिष्ठ नागरिकों की संयुक्त संघर्ष समिति का गठन करना तथा मीटिंग एवं अधिवेशन आयोजित करना।

दैनिक यात्रियों पर रेलवे निजीकरण का दुष्प्रभाव

- भारतीय रेल के यात्रियों में दैनिक यात्रियों की संख्या बहुत ही ज्यादा है जिनकी पूरी जीवन रेल पर ही निर्भर होता है ये साधरणतः बहुत ही मध्यम वर्ग व मजदूर वर्ग के यात्री होते है।ये वे लोग है जो छोटे छोटे शहर से व गांव से बड़े शहर में जाकर अपना रोजी रोटी चलाते है,नौकरी करते है व शाम को वापस अपने घर आ जाते है। इनके लिये सबसे ज्यादा मायने समय की बचत व सस्ते किराया का होना है भारतीय रेल।इन्हें बहुत ही कम दर पर मासिक सीजन टिकट व त्रैमासिक सीजनटिकट की सुविधा दी गई है साथ ही उक्त टिकट पर एक निश्चित वजन के समान भी लाने ले जाने की सुविधा दी गई है । ये वर्ग रेलवे की सुरक्षा व संरक्षा में भी काफी महत्व रखते है । रेलवे की सुरक्षा समितियों में भी इनकी सदस्यता रहती है । निजीकरण के बाद इस प्रकार की मासिक सीजन टिकट में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी व जरूरी नही की इनके समयानुसार गाड़ी चलाई जाएगी इन पर रेल यात्रा के ऊपर अत्यधिक आर्थिक बोझ बढेगा

दैनिक यात्रियों के साथ गतिविधि

- यूनियन के पदाधिकारियों को दैनिक यात्री संघ के सदस्यों से मिलकर उन्हें इससे होने बाली नुकसान से अबगत कराया जाय इन्हें पोस्टर, पम्पलेट दिया जाय जिसे वे अपने शहर व गाँव मे लगाकर दैनिक यात्री को इस निजीकरण के विरुद्ध होने वाले जनांदोलन के लिये जागरूक व तैयार किया जा सके इन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से भी विरोध जारी करने के लिये उत्साहित की जाए।
- दैनिंक यांत्रियों की संयुक्त संघर्ष समिति का गठन करना तथा मीटिंग एवं अधिवेशन आयोजित करना।

श्रमिक वर्ग पर रेलवे निजीकरण का दुष्प्रभाव

आर्थिक मंदी व कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति का सबसे बुरा प्रभाव श्रमिक वर्ग पर ही हुआ है। जहॉ लॉक डाउन के कारण लधु एवं मझौले उद्योग–धंधे बंद हो गये हैं और आर्थिक स्थिति के कारण निकट भविष्य मे उनका उभरना भी कठिन दिख रहा है। और श्रमिक वर्ग को रोजगार से हाथ धोकर अपने– अपने गॉव कस्बे को पलायन करना पड़ा है। ऐसी स्थिति मे रेल का निजीकरण होने से सबसे बुरा प्रभाव श्रमिक वर्ग पर ही पड़ेगा। यदि श्रमिक वर्ग को वापस अपने कार्यक्षेत्र मे रोजगार की तलाश मे जाना पड़ा तो डाइनैमिक फेयर व्यवस्था का सबसे बुरा प्रभाव इसी वर्ग पड़ेगा। साथ ही भारत सरकार ने पाईवेट ट्रेन आपरेटरों को अधिकतम किराया तय करने की कानूनी शक्ति प्रदान करने का आश्वासन दिया है। जिससे निजी ट्रेन संचालन करने वाला आपरेटर कभी भी मनमाना किराया बढ़ा सकता है। जिसे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

- माल भाड़ा बढ़ने से भी विपरीत असर श्रमिक वर्ग पर ही पडेगा क्योंकि माल भाड़ा बढ़ने से मंहगाई में बढ़ोत्तरी होगी और श्रमिक वर्ग का जीवन यापन बहुत कठिन हो जायेगा।
- निजीकरण से रोड साईड स्टेशनो, कस्बो एवं बड़े शहरों मे रोजगार हेतु प्रतिदिन आने–जाने वाले यात्रियों (श्रमिको) का आवागमन का सस्ता एवं सुलभ साधन छिन जायेगा।
- स्टेशनों का निजीकरण होने से रोजगार हेतु दिन–प्रतिदिन आने वाले श्रमिको को प्लेटफार्म टिकिट एवं वाहन स्टैण्ड का चार्ज बढ़ने से उन पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
- रिक्शा चालक, आटो रिक्शा चालक का स्टैण्ड शुल्क मंहगा हो जायेगा।

- कुली पर अतिरिक्त शुल्क लगेगें।
- प्रतिदिन बड़े शहरों मे मजदूरी के लिये आने–जाने वाले अप–डाउन की डैज एवं अन्य सुविधायें खत्म हो जायेगी या बहुत महंगी हो जायेगी।
- दिव्यांग जनों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गो, मरीजो, जैसे कैन्सर पीड़ित आदि को मिलने वाली रियायतें खत्म हो जायेगी।
- खेलो मे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को रेलवे स्थाई नौकरी प्रदान करती है। निजी हाथो मे जाने से खिलाड़ियों के लिये सुरक्षित स्थाई नौकरी की समस्या पैदा होगी।

- इसके अतिरिक्त नये उभरते हुये खिलाड़ियों को रेलवे द्वारा यात्रा मे रियायत दी जाती है, जो समाप्त हो जायेगी।
- लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ मीडिया पर रेल के निजीकरण का विपरीत प्रभाव पड़ेगा। पत्रकार एवं अन्य मीडिया कर्मियो को मिलने वाली रियायतें समाप्त हो जायेगी।

- देश मे असंगठित क्षेत्र मे लगभग 48.7 करोड़ श्रमिक वर्ग से आते है जिनके औसत आय के बात करे तो लगभग 6 से 12 हजार के बीच इनकी औसत आय है। तो वे लोग सीधे तौर पर प्रभावित होगें। इसे आसान भाषा मे समझे तो निजीकरण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश की लगभग 37 फीसदी आवादी के बुरे दिन आने वाले है। कैसे, निम्न बिन्दु से समझते है :—

1. मनमाना हॉल्ट–कम्पनियॉ अपने फायदे के हिसाब से हॉल्ट निधार्रित करेगी। जिससे छोटे स्टेशन के श्रमिक सीधे तौर पर प्रभावित होगे। क्योकि वे रोजगार की तलाश मे बड़े शहर मे जाते है। और इनका रोजाना ट्रेनो के माध्यम से आना जाना होता है।
2. मनमाना समय सारणी प्रबंधन–प्राईवेट ट्रेनो के मालिक अपने हिसाब से समय सारणी तय करेगे। जिससे श्रमिक वर्ग को अपने कार्य स्थल तक पहुॅचने मे देरी हो सकती है या काफी समय देना पड़ सकता है।

4. श्रमिको के हितो की उपेक्षा–सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति जबावदेह होती है लेकिन प्राईवेट कम्पनियॉ आपने निजी फायदो छोड़कर किसी की भी परवाह नहीं करती है। जिससे समाज मे जो गरीब है वे और भी गरीब होते चले जायेगे। जो अमीर है वे और अमीर होते चले जायेगे। इसे ऐसे समझे कि ठेकेदारो को सस्ते से सस्ता श्रमिक चाहिये। जिससे समाज मे गरीब और अमीर के बीच एक बहुत ब़डी खाई उत्पनी होगी। जो किसी भी देश के सेहत के लिए ठीक नही है।
5. जॉब सेक्युरिटी मे कमी– आज रेलवे मे जो भी श्रमिक निजी तौर पर काम करते है या उसके परिधि क्षेत्र मे आते है उनकी सेक्युरिटी मे कमी आयेगी। जिससे उनका शारीरिक और आर्थिक शोषण हो बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर– वर्तमान समय के परिपेक्ष्य मे हर एक निजी कर्मचारी कहीं न कहीं सरकारी तंत्र के अंतर्गत ही है। या समझे इनका तार कहीं ना कहीं सरकारी रेल तंत्र के होते हुए सरकार से जुड़ा होता है। जिससे उनका जॉब सेक्युरिटी कभी हद तक बरकरार है।

- कोरोना काल मे रेल का निजीकरण एक षडयंत्र का कदम–

जब कोरोना महामारी नहीं थी तब भारत के श्रमिक वर्ग अपने घरो, कस्बो, गॉव, अपने पैतृक भूमि को छोड़कर भारत की अर्थ व्यवस्था बढाने और नई ऊँचाई प्रदान करने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिये। लेकिन जब समाज के सभी वर्गो मे सबसे उच्च स्थान श्रमिक वर्ग का है। तब सरकार कहीं ना कहीं अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। और इसी कदम मे रेलवे का निजीकरण भी एक कदम है। कोरोना के इस काल मे श्रमिक स्पेशल ट्रेने तभी चलाई जा सकी और श्रमिको को अपने गन्तव्य तक सकुशल सुरक्षित पहुँचाया गया। जब ये सरकारी हॉथो मे थी। लेकिन निजीकारण के बाद इसकी कल्पना ही हास्यपद है। क्योकि कम्पनियॉ सिर्फ अपना फायदा देखती है।

श्रमिक वर्ग के साथ गतिविधि

- शहरों/कस्बों के असंगठित/संगठित क्षेत्र के श्रम संगठनों/कार्यकारणी के साथ बैठक आयोजित की जाये। जिसमें निम्न रूप रेखा तय हो।
- प्रतिनिधियों का समस्त ब्यौरा रजिस्टर मे दर्ज किया जाये।
- श्रम संगठन पदाधिकारियों से उनके कार्यक्षेत्र मे जन सम्पर्क अभियान की तारीख एवं समय निर्धारित किया जाये।
- सामूहिक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जाये। और उसके लिये बैनर/पोस्टर लगाये जायें एवं पोस्ट कार्ड भेजा जाये।
- सयुंक्त संघर्ष समिति के साथ भागीदारी करना।

खिलाड़ी/कलाकार/पत्रकार/मीडियाकर्मी बुद्धिजीवी वर्ग पर रेल निजीकरण का दुष्प्रभाव

कोरोना एवं उसके दुष्परिणाम के फलस्वरूप आर्थिक मंदी का गंभीर असर देश के खिलाड़ियों, कलाकारों एवं मीडिया कर्मियों पर पड़ा है। कोरोना के कारण लगाने गये लॉक डाउन (डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट) के कारण खेल व सांस्कृतिक गतिविधियॉ ठप्प हैं, एवं मीडियॉ कर्मियो की छटनी की जा रही है अर्थात उनके जीवनयापन पर गंभीर असर पड़ा है। गतिविधियॉ सामान्य होने पर सबसे ज्यादा आवागमन इन्हीं वर्ग के लोगों को करना पड़ता है और भारतीय रेलवे इन वर्ग के लोगो को टिकिट मे विभिन्न रियायतें देती आई है। जो कि 25 से 75 प्रतिशत तक विभिन्न श्रेणियों मे दी जाती है। अतः भारतीय रेल का निजीकरण होने पर इन वर्ग के यात्रियों को जो कि आर्थिक मंदी के शिकार पहले से ही है। आर्थिक तौर पर और कमजोर करेगी। प्राईवेट ट्रेन आपरेटर ना तो इस वर्ग को किराये मे कोई रियायत देगा और ना ही प्राथमिकता। प्राईवेट ट्रेन आपरेटरों द्वारा डाइनेमिक फेयर पद्धति से अधिकतम किराया वसुलने की छूट रहेगी। जिसका प्रभाव खिलाडियों, कलाकारो, व पत्रकारों/मीडिया कर्मियो पर भी रहेगा। और आवागमन का शुलभ एवं सस्ता साधन छिन जायेगा। स्टेशनों के निजीकरण से प्लेटफार्म टिकिट व वाहन स्टैण्ड चार्ज बढ़ने से प्रभाव भी इन वर्ग के लोगो पर अधिक पड़ेगा, क्योकि इनका आवागमन स्टेशनों मे अपने कार्य से संबंधित अधिक रहता है।

- वर्तमान युग मे इस बात से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता की लगभग हर प्रसिद्ध मीडिया हाउस के उपर कहीं ना कहीं बड़ी निजी कम्पनियो की हिस्सेदारी होती है। जिस कारण से पत्रकार चाहते हुए भी कम्पनियों मे पनप रहे भष्टाचार, शोषण, गड़बड़ी के खिलाफ मुखर होकर आवाज नहीं उठा पाते और यह वहीं कम्पनियॉ होती है जो कि रेलवे के निजीकरण मे भागीदारी है/होगें तो क्या हम ऐसे भरोसा कर सकते है। कि रेलवे का निजी करण होने के बाद उसे प्रर्याप्त गड़गड़ियॉ भ्रष्टाचार अफसरशाही का स्वंतत्र पत्राकार खुलकर विरोध कर पायेगे? उत्तर है नहीं
- छोटे गॉव जिलो मे कनेक्टिविटी की कमी– चुकी निजीकरण होने से निजी कम्पनियॉ देश के वहीं हिस्सों मे प्राइवेट ट्रेनो का संचालन करेगे। और बढ़ायेगे जहॉ उन्हें जल्दा मुनाफा होगा। जिससे भारत के ग्रामीण क्षेत्र और कम विकसित क्षेत्र प्रभावित होगे।

खिलाड़ी/कलाकार/पत्रकार/मीडियाकर्मी बुद्धिजीवी वर्ग के साथ गतिविधियां

1. विभिन्न क्षेत्रों के नामी खिलाडी/ कलाकारों/ पत्रकारों/बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से व्यक्तिगत संघर्ष करना। रेलवे के निजीकरण से होने वाले समाज पर दुष्प्रभावों के बारे में चर्चा करना।
2. उनको निजीकरण के विरोध में चल रहे जन अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों में मेहमान के रूप में वक्ता के रूप में आमंत्रित करना।

3. निजीकरण के विरोध में उनके वक्तव्य हासिल करना तथा मीडिया से संप्रेषित करना।
4. निजीकरण के विरोध में उनके वीडियों हासिल करना एवं सोशल मीडिया पर प्रसारित करना।
5. आन्दोलन की जन समिति में उनको स्थान देना।
6. खिलाड़ी एव सांस्कृतिक से संबंध रखने वाले लोगों की समिति बनाना और उन्हें निजीकरण विरोधी आन्दोलन के कार्यक्रम में शामिल करना।
7. विभिन्न प्रिंट मीडिया के पत्रकारों से सम्पर्क करना एवं निजीकरण के पक्ष में यह रखने वाले पत्रकारों के साथ प्रिन्ट मीडिया से निजीकरण विरोध खबरों को प्रमुखता देने के लिये आव्हान करना।
8. समय समय पर प्रेस वार्ता आयोजित करना और उसमें मीडिया कर्मियों को अपने पक्ष में जुटाना

निजीकरण के सभी वर्गो पर नकारात्मक प्रभाव

- प्रोफिट मैकिंग–निजी मालिको का एकमात्र उधेश्य लाभ कमाना है और वे किसी भी कीमत पर इसे प्राप्त करने की कोशिश करते है क्याकि यह उत्पाद की गुणवत्ता से समझौता करता है। ग्राहक की भावनाओं के साथ खेलता है। या अन्य अनुचित साधनो को अपनाता है।
- कीमत बढ़ना– ऐसे क्षेत्रो मे जहॉ निजी कम्पनी स्वांमी की प्रतिर्स्पधा या एका अधिकार कम है। उपभोत्तओं को सामान और सेवाऐं खरीदने के लिए बड़ी मात्रा मे धनराशि की आवश्यकता होती है कीमतो मे बढ़ोत्तरी है और ग्राहको के पास भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
- भ्रष्टाचार मे वृद्धि– निजी मालिक अपने कार्यो को पूरा करने के लिए विभिन्न माध्यमो को अपनाते है। वे रिश्वत, धोकाधड़ी और कई अन्य ऐसे बुरे काम करते है जो भ्रष्टाचार को जन्म देते है।

- पारदर्शिता की कमी– एक लोकतांत्रिक सरकार मे जनता सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए सरकार से सवाल कर सकती है। और सरकार स्पष्ट तश्वीर दिखाने के लिए बाध्य है। हालकि निजी क्षेत्र के संगठन ऐसे किसी भी कानून से बाध्य नहीं है। और इस प्रकार पारदर्शिता का अभाव है।
- अस्पष्टता– निजीकरण ने विभिन्न क्षेत्रो के साथ कई विकल्प चुने है। सामान्य वास्तुओ और सेवाओं को विभिन्न निजी क्षेत्र के मालिको द्वारा विभिन्न दरों, गुणवत्ता और विविधता पर पेश किया जाता है। जिससे ग्राहक भ्रम होता है।

एन.जी.ओ. एवं जन समितियॉ पर रेल निजीकरण का दुष्प्रभाव

- निजी रेलो मे एन.जी.ओ. एवं जन समितियों को अपने लोक हित कारी उद्देश पूर्ण करने में कठिनाई होगी। जैसे–प्लेटफार्म आदि पर कैम्प आदि लगाकर किये जाने वाले कार्यो में बाधा उत्पन्न होगी एवं उनकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का प्रयास करने का प्रयास किया जायेगा।

- वर्तमान भारत मे मौजूद बहुत सारे एन.जी.ओ. के लिए भारतीय रेलवे अपने निजी फायदे को छोड़कर उन्हें समाज सेवा से जुड़ने का मौका प्रदान करती है जैसे असम केरल बिहार मे आई बाढ़ के दौरान जरूरी सहायता सामानों को भारतीय रेल के जरिए देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक एनजी.ओ. की सहायता से पहुँचाया जा सका। जबकि निजी करण होने के बाद रेलवे से इस तरह की मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती।

दिव्यांग वर्ग पर रेलवे निजीकरण का दुष्प्रभाव

1. भारतीय रेल दिव्यांग यात्रियों के लिये भी रेल यात्रा में विशेष सुविधा देती है रेल्वे इनके प्रत्येक यात्री गाड़ियों में एक अतिरिक्त डिब्बे लगाती है। साथ ही इनको बहुत ही कम किराये पर टिकट उपलब्ध कराती है साथ ही एक सहायक को भी इनके साथ यात्रा की सुविधा दी गई है । आरक्षित डिब्बे में भी इनके लिये अतिरिक्त बर्थ आरक्षित है। इनके लिये स्टेशनों पर अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है । इनका भारत मे अपना एक अलग बड़ा संगठन है जो इनके लिये कार्य करती है ।
2. निजी कम्पनी अत्यधिक मुनाफे कमाने के चक्कर मे ये सुविधा बन्द कर सकती है व अतिरिक्त डिब्बे से होने बाले नुकसान के कारण डिब्बे भी हटा सकती है।

3. इनके लिये रेल में दिव्यांग हेतु अलग से पूरा कोच होता है जिसमें व्हील चेयर से जाने का प्रावधान है जो कि समाप्त हो जायेगा ।
4. वर्तमान में रेल्वे (0.30रू. प्रति किमी. अनारक्षित टिकिट) टिकिट है जबकि अन्य परिवहन इत्यादि 04 रू. प्रति किमी. हो जो कि लगभग 13 गुना ज्यादा है ।
5. विकलांग व्यक्तियों को समझाना होगा, कि किसी भी प्राईवेट व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली ट्रेन में ना ही उन्हैं किसी भी तरह कि सबसिडी मिलेगें और नही ट्रेन में आरक्षित जगह मिलेगी ।
6. हमे विकलांग लोगों की जो लिपी होती है जानकार व्यक्ति को बूलाकर उन्हैं समझाना होगा ।

दिव्यांग वर्ग के साथ गतिविधि

- यूनियन के पदाधिकारियों को इनके संगठन के पदाधिकारियों से मिलकर इनकी बैठकर इन्हें इस बाबत जानकारी दी जाय दिव्यांग कोच में विरोध के पोस्टर लगवाए जाए व जनांदोलन में सहयोग कर उन्हें इससे होने बाले नुकसान के खिलाफ आवाज बुलन्द करने के लिये आगे आने को कहा जाय

रेलकर्मचारियों पर निजीकरण का रेल पर दुष्प्रभाव

- रेलवे के निजीकरण के पश्चात रेल कर्मचारी को नौकरी से हटाने का खतरा सदैव बना रहेगा।
- निजीकरण कि त्रीवता से सरकारी कर्मचारी कभी भी प्राईवेट कम्पनी के कर्मचारी में बदला जा सकता है।
- निजीकरण होने से रेलवे कर्मचारी की जो सिक्योरिटी(नौकरी की सुरक्षा) व स्थायित्व स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- रेल कर्मचारियों को मिलने वाली आकर्षक वेतन एवं भत्ते व अन्य सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- रेल कर्मचारियों को भी भविष्य में प्राईवेट कम्पनीयों द्वारा निर्धारित एक–चौथाई वेतन तथा अधिकतम कार्य करना होगा।
- निजीकरण के पश्चात देश के श्रम कानूनों का संरक्षण कर्मचारियों को प्राप्त नहीं होगा।

- निजीकरण के बाद रेल कर्मचारियों व इनके परिवार को यात्रा हेतु पास/पी.टी.ओ. तथा अन्य सुविधाओं में कटौती या उनसे वंचित कर दिया जाएगा।
- निजीकरण के पश्चात ओल्ड पेंशन व न्यू पेंशन (एनपीएस) स्कीम में आने वाले कर्मचारियों को पेंशन मिलती रहने की कोई गारंटी नहीं रहेगी।
- रेल के निजीकरण के पश्चात रेल कर्मचारियों के परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति एवं लार्जेज के अन्तर्गत नौकरिया मिलना खत्म हो जाएगी।

- निजीकरण के प्श्चात रेल कर्मचारियों के होनहार बच्चों को स्पोर्ट क्वोटा स्काउट क्वोटा, सांस्कृतिक सैकिन क्वोटा, तथा दिव्यांग क्वोटा में भर्तिया समाप्त हो जाएगी।
- देश में घटित असामान्य परिस्थितियों एवं युद्ध के समय रेल कर्मचारी टेरोटोरियल आर्मी के माध्यम से सैनिको के साथ देश की सेवा करता है निजीकरण होने पर देश उनकी सैनिक सेवाओं से वंचित हो जाएगा।
- निजीकरण को पूरी तरह रेलवे में लागू करने हेतु सरकार द्वारा कर्मचारियों को उनकी सेवा मुल्यांकन के नाम पर जबरन अनिवार्य सेवानिवृति देने की साजिश रची जा रही है।
- यूनियन द्वारा रेल कर्मचारी के एक बच्चे को नौकरी देने की लड़ाई का सपना केवल सपना ही रह जाएगा।
- निजीकरण के पश्चात कर्मचारियों को प्रतिमाह समय पर वेतन एवं अन्य भत्ते मिलने की काई संभावना नहीं रहेगी।

- बोनस (पीएलबी) भी बंद हो जायेगा।
- रेलकर्मचारियों को एवं उनके परिवारों को मिलने वाली निशुल्क चिकित्सा सुविधा बन्द हो जायेगी।
- रेल कर्मचारियों को मिल रही कल्याणकारी सबंधित योजनायें एवं कॉऑपरेटिव सोसायटी जैसे (एसबीएफ, जेसीसीएस, जेपी बैंक डब्ल्यूसीआरईसीसीएस इत्यादि) रेल संस्थान, होलीडे होम्स इत्यादि स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- रेलवे की जमीन एवं आवासों की कर्मचारियों को मिल रही सुविधा छिन जायेगी।
- मजदूरों के हित में यूनियन की नेगोशियटिंग मशीनरी की बार्गेनिंग पावर क्षीण होने की संभावना होगी।

रेलकर्मचारियों के साथ गतिविधयां

- तीनों मण्डलों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों का केटेगरी वाईज नवीनतम डेटाबेस तैयार करा जाये।
- यूनियन द्वारा निजीकरण के दुष्परिणामों एवं संघर्ष हेतु आन्दोलन की रूपरेखा की सामग्री बनाई जाये (**Leaflet, Booklet & Posters**) की सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी दोनों
- महामंत्री एवं अध्यक्ष द्वारा तीनों मण्डलों के सभी शाखा सचिव एवं अध्यक्षों के साथ मीटिंग आयोजित कर विस्तृत चर्चा करें।

- प्रत्येक मण्डल में सभी शाखा–स्तर पर मीटिंग (पदाधिकारीयों के साथ)आयोजित की जाये।
- यूनियन के मुख्यालय/मण्डल के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मण्डल की यूथ विंग महिला विंग के साथ मीटिंग आयोजित की जाये।
- निजीकरण को रेलवे में जन आन्दोलन बनाने हेतु तीनों मण्डलों की प्रत्येक शाखा से न्यूनतम 5 वक्ताओं का चयन किया जाये। तथा उनको आन्दोलन की समस्त रूप रेखा बताने हेतु प्रशिक्षण कक्षा (3) दिन का आयोजन किया जाये।
- कैम्पेनिंग के लिये प्रत्येक शहर में टारगेट क्षेत्र एवं कार्यस्थल चिन्हित किये जायें।
- चिन्हित टारगेट क्षेत्र में संघर्ष अभियान को जन चेतना जागृत करने हेतु पृथक–पृथक टीम (ऑफिस बियरर, युवा, महिला एवं स्पीकर) का निर्धारण किया जाये

- निर्धारित प्रत्येक टीम अपने टारगेट क्षेत्र में समान्त जाकर जनसम्पर्क करेगी तथा सामग्री के साथ कार्यस्थलों पर एवं आवासों पर जाकर जनसम्पर्क करेगी तथा सामग्री वितरण एवं प्रत्येक परिवार का बायोडेटा संग्रहित करेगी।
- प्रत्येक टीम जनसम्पर्क अभियान के पश्चात एकत्रित बायोडेटा को यूनियन के मण्डल कार्यालय में सुपूर्द करेगी।
- रेल परिवार के विद्यार्थी एवं बेरोजगार बच्चों एवं महिलाओं को जन आन्दोलन के संघर्ष से जोड़ने हेतु धार्मिक/सांस्कृतिक एवं महापुरूषों की जयन्ती आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाये।
- रेल कर्मचारियों को निजीकरण के खिलाफ संघर्ष में अहम भूमिका निभाने हेतु मण्डल स्तर पर शाखा स्तर पर गेट वीटी एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किये जायें।

वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलाईज यूनियन

दिनांक 14 से 19 सितम्बर

रेल निजीकरण के खिलाफ

जनसम्पर्क सप्ताह कार्यक्रम

Dt. 14.09.2020

ब्लैक आउट

रात्रि 08.00 बजे से 08.10 तक सभी अपने मकानों की लाईटें बन्द करेगें।

Dt. 15.09.2020

सभी शाखायें अपने–अपने कार्यस्थल पर गेट मीटिंग का आयोजन करेगें।

जो भी समय उपयुक्त हो।

Dt. 16.09.2020

सभी चिन्हित वर्गों से जनसम्पर्क करना है।

1. व्यापारी
2. युवा वर्ग
3. विद्यार्थी वर्ग
4. महिला वर्ग
5. पेंशनर्स एवं वरि. नागरिक
6. दैनिक यात्री
7. श्रमिक वर्ग
8. खिलाडी, कलाकार, पत्रकार एवं मीडिया कर्मी
9. बुद्धिजीवि वर्ग (प्रोफेसर, जज, एडवोकेट, डाक्टर)
10. एनजीओ एवं जन समितियां
11. रेलकर्मी
12. राजनैतिक दल
13. अनुसूचित जाति
14. अनुसूचित जनजाति
15. पिछड़ा वर्ग

Dt. 17.09.2020

मोटरसाईकिल रैली

Dt. 18.09.2020

मशाल जुलूस

Dt. 19.09.2020

1968 की रेल हड़ताल के अमर शहीदों को श्रंद्धाजलि स्वरुप Twitter कार्यक्रम

मॉस गेट टू गेदर

जनआंदोलन के सभी वर्गों के साथ